

# नई शिक्षा नीति लागू करने में लविवि बनेगा मददगार

परास्नातक में मल्टी एग्जिट की सुविधा देने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनने पर मार्गदर्शन लेने आई मध्यप्रदेश की टीम

सचिन त्रिपाठी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय परास्नातक स्तर पर मल्टी एग्जिट की सुविधा देने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इसके बाद विश्वविद्यालय एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लविवि मध्यप्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में सहयोग करेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश की टीम ने पिछले सप्ताह विवि का दौरा किया। इस दौरान टीम ने कुलपति तथा नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए बनी समिति की सदस्य व लविवि की अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. पूनम टंडन से मुलाकात की।

देश में 36 साल के लंबे अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसके प्रावधान पूरी तरह लागू करने के लिए पाठ्यक्रम



“लविवि करेगा दूसरे संस्थानों की सहायता

पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश की टीम ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मुलाकात की और यहां लागू प्रावधानों पर चर्चा की। लविवि परास्नातक स्तर पर मल्टी एग्जिट की सुविधा देने वाला देश का पहला विवि बन गया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य संस्थानों को नई शिक्षा नीति लागू करने में मदद करें।

—प्रो. आलोक कुमार राय, कुलपति लविवि

में बड़े बदलाव की जरूरत है। लविवि ने इसे समझते हुए वर्तमान सत्र से ही इसे परास्नातक स्तर पर लागू कर दिया है। नई शिक्षा नीति में अन्य बिंदुओं के साथ एक बड़ा बिंदु मल्टी एग्जिट की सुविधा देना है। इसके अनुसार

विद्यार्थी को किसी भी स्तर पर परीक्षा पास करके पाठ्यक्रम छोड़ने का विकल्प दिया जाता है। विद्यार्थी को उसके द्वारा पढ़े गए सिलेबस के आधार पर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और डिग्री देने की व्यवस्था है।

कुलपति व अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने टीम को दिया सहयोग का आश्वासन

लविवि ने स्नातक स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि परास्नातक स्तर पर इसे लागू कर दिया है। इसके साथ ही चौंस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अन्य संकाय के विषय पढ़ने की आजादी, वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई के साथ ही मूल्य आधारित शिक्षा को भी सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। ऐसा करने वाला लविवि देश का पहला विश्वविद्यालय है। इसीलिए मध्य प्रदेश की टीम ने लविवि का दौरा करके मार्गदर्शन लिया है। इस टीम में अजय प्रकाश खरे, संजय जैन तथा दिवा मिश्रा शामिल थे।

स्नातक स्तर के लिए तैयार हो रहा सिलेबस

लविवि ने दाखिले में देरी होने की वजह से परास्नातक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को शामिल कर लिया है। इस समय स्नातक स्तर पर इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। स्नातक में विद्यार्थियों की संख्या परास्नातक की तुलना में बेहद ज्यादा है। अगले सत्र से चार अन्य जनपदों के कॉलेज भी लविवि के पाठ्यक्रम से पढ़ाई करेंगे। ऐसे में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों की कुल संख्या करीब ढाई लाख हो सकती है। स्नातक स्तर पर जो भी बदलाव होंगे वे सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगे। इसलिए लविवि इस पर भी ध्यान दे रहा है कि प्रावधान नई शिक्षा नीति के हिसाब से होने के साथ ही व्यवहारिक भी होने चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से लागू किया जा सके।

# शिक्षित बेटियां ही देंगी समाज को सही दिशा : प्रो. राय

शहर में कई जगह मिशन शक्ति कार्यक्रम, लखनऊ विवि में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत  
माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। शिक्षित बेटियां ही समाज को सही दिशा दे सकती हैं। समाज को आगे ले जाने में बेटियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। आज बेटियां हर क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र हो या खेलकूद सभी जगह अपना परचम लहरा रही हैं। देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये बातें मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कही। वह राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व समाज कार्य विभाग की ओर से मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित 'सशक्त एवं सुरक्षित नारी' का संदेश देते हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पोस्टर मेकिंग एवं स्लोगन राइटिंग प्रदर्शनी को भी देखा।

प्रो. राय ने स्वयंसेवकों द्वारा बनाये गए सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाते हुए सभी को महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण का संदेश दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉ. अशोक श्रोती क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना थे। कार्यक्रम में प्रो. पूनम टंडन, प्रो. एके भारतीय, डॉ. राकेश द्विवेदी, डॉ. अंशुमाली शर्मा, डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव, डॉ. कुसुम यादव, डॉ. रूपेश कुमार, डॉ. किरण शर्मा, डॉ. विभावरी सिंह, डॉ. मोहिनी गौतम आदि उपस्थित थे। लविवि के इंजीनियरिंग संकाय द्वारा इसी विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डेंटल सर्जन डॉ. हिमांगी दुबे ने 'ओरल हाइजीन फॉर वुमंस' पर जागरूक किया। कार्यक्रम में ज्योत्सना कुमार हबीबुल्लाह, निधि श्रीवास्तव, कल्पना पटेल ने भी संबोधित किया।



हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय।

AMRIT VICHAR PAGE 3

लविवि में मार्च में ही होंगी स्नातक की शेष परीक्षाएं

अमृत विचार लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र को पटरी पर लाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। विवि का परीक्षा विभाग सत्र को पटरी पर लाने के लिए कसर कस ली है। इसके लिए स्नातक की शेष परीक्षाएं मार्च में कराने की तैयारी चल रही है ताकि आगामी सत्र से नियत समय पर शुरू किया जा सकता है।

कोरोना काल के चलते शासन की ओर से गत वर्ष लाकडाउन घोषित किया गया था, जिसके कारण सत्र की पढ़ाई आनलाइन चल रही है और साथ ही परीक्षा आनलाइन कराने की तैयारी भी लेकिन परीक्षा तक कोरोना के संक्रमण की हालात में काफी सुधार होने से ऑफलाइन परीक्षा कराया जा रही है। हालांकि सेमेस्टर की परीक्षा आनलाइन मोड पर कराया गया है। फिलहाल सत्र को

पटरी पर लाने के लिए विवि प्रशासन प्रयास कर रहा है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. एएम सक्सेना ने बताया कि सत्र को पटरी पर लाने के लिए परीक्षा को जल्द निपटाने का प्रयास जारी है।

THE PIONEER PAGE 4

UP's first population clock comes up at university

PNS LUCKNOW

Uttar Pradesh's first population clock was inaugurated at gate number 2 of Lucknow University by Minister of State for Health and Family Welfare Ashwini Kumar Choubey and state's Health Minister Jai Pratap Singh on Tuesday.

Director of Population Research Centre and head of LU's Economics department Prof MK Agarwal said the aim of setting up the clock at a vantage point is to make people aware that the population figure is ticking over.

"Everyone can look at the clock, be it someone commuting on the road or by metro. Since its installation, it has also become a selfie point. This clock will spread awareness about the fact that the population of the country has increased to 1.39 billion. We have placed a caption 'Population of India today' over the clock," he said.

Agarwal said the figures given by the clock are projected figures and the clock is programmed by the department. "We will update further with more programming. It is not the exact birth that is recorded every second but the likely figure which we get through projection. We have data coming from various sources and we revise the projection of figures accordingly," he pointed out. He said they were able to set up the clock at a cost of Rs 1.5 lakh.

Agarwal said they also got Rs 5 crore from the Central government for the construction of Population Research



Centre building. "Currently, the centre operates from the Economics department," he said.

Meanwhile, the Population Research Centre (PRC), department of Economics, also held a knowledge dissemination workshop at the university. The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has established the network of 18 Population Research Centres (PRCs) spread over 16 major states, with the mandate to provide, inter alia, critical research-based inputs related to the health and family welfare programmes and policies at state and national levels. The PRCs are autonomous in nature and administratively under the control of their host universities and institutions, Agarwal said.

A mobile app called RCH-ANMOL was also launched, as were the logo of PRC and its website.

Choubey highlighted the important role of evidence-

based research in success of health policy, especially in Covid-19 times. He underlined that the government is running several schemes to enable the reach of health facilities to the bottom section of the population. He mentioned the importance of research as 'Jai Anusandhan' along with 'Jai Jawan, Jai Kisan and Jai Vigyan'. JP Singh highlighted the success of the state government in handling the pandemic through digital initiatives, and RCH-ANMOL app is the latest one. LU Vice-Chancellor Prof AK Rai stressed on the need of better infrastructure facility and teaching staff for the PRC.

The keynote speaker was Dr DK Ojha, director general of Statistics, Government of India. He highlighted the recent and most appropriate research done by different PRCs of the country. The session was also attended by mission director, NHM (UP), MS Aparna Chaudhari.

RASHTRIYA SAHARA PAGE 5

शिक्षित बेटियां ही समाज को दे सकती हैं सही दिशा : कुलपति

लखनऊ (एसएनबी)। राष्ट्रीय सेवा योजना, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं समाज कार्य विभाग के दो दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने सशक्त एवं सुरक्षित नारी का संदेश देते हुए हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने पोस्टर मेकिंग एवं स्लोगन लेखन प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने उद्बोधन में कहा कि शिक्षित बेटियां ही समाज को सही दिशा दे सकती हैं और समाज को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

विशिष्ट अतिथि डा. अशोक श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना ने विचार व्यक्त किए। संचालन कर रहे डा. राकेश द्विवेदी, कार्यक्रम समन्वयक ने बताया कि मिशन शक्ति केवल लड़कियों को जिम्मेदारी नहीं है इसमें लड़कियों की सहभागिता भी उत्तरी हो आवश्यक है तभी हम जेडर न्यूट्रल समाज बना पाएंगे। उन्होंने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में 1 मार्च 2021 को महिला सुरक्षा विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें डा. संगीता शर्मा, सदस्य, बाल कल्याण समिति ने महिला एवं



बालिकाओं से विभिन्न समस्याओं का जिक्र करते हुए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं व हेल्प लाइन के बारे में चर्चा की, उन्होंने छात्र छात्राओं के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर भी दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डा. अंशुमाली शर्मा ने कहा कि हम जब तक जे जे एक्ट, पौक्सो एक्ट आदि कानूनों को नहीं जानेंगे तब तक पूरी तरह किसी भी पीड़ित की मदद नहीं कर पाएंगे। पोस्टर मेकिंग एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कार्यक्रम के प्रथम दिन 1 मार्च 2021 को किया गया, जिसमें कुल 163 छात्र एवं छात्रा ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में डा. दुर्गेश श्रीवास्तव, डा. रूपेश कुमार, कुसुम यादव, डा. किरण शर्मा, डा. विभावरी सिंह, डा. मोहिनी आदि मौजूद रहे।

VoL PAGE 6

सत्र पटरी पर लाने के लिए परीक्षा कराने की तैयारी

यथेष्ट संवाददाता (VOL)

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र को पटरी पर लाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। विवि का परीक्षा विभाग सत्र को पटरी पर लाने के लिए कसर कस ली है। इसके लिए स्नातक की शेष परीक्षाएं मार्च में कराने की तैयारी चल रही है ताकि आगामी सत्र से नियत समय पर शुरू किया जा सकता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र को पटरी पर लाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। विवि का परीक्षा विभाग सत्र को पटरी पर लाने के लिए कसर कस ली है। इसके लिए स्नातक की शेष परीक्षाएं मार्च में कराने की तैयारी चल रही है ताकि आगामी सत्र से नियत समय पर शुरू किया जा सकता है। कोरोना काल के चलते शासन की ओर से गत वर्ष लाकडाउन घोषित किया गया था, जिसके कारण सत्र की पढ़ाई आनलाइन चल रही है और साथ ही परीक्षा आनलाइन कराने की तैयारी भी लेकिन परीक्षा तक कोरोना के संक्रमण की हालात में काफी सुधार होने से ऑफलाइन परीक्षा कराया जा रही है। हालांकि सेमेस्टर की परीक्षा आनलाइन मोड पर कराया गया है। फिलहाल सत्र को